TIBETAN YOUTH CONGRESS

तिब्बती युवा कांग्रेस: 'ब्लैक हैट मार्च' पर आधिकारिक बयान

ब्लैक हैट मार्च तिब्बत पर चीन के अवैध और ज़बरदस्ती किए गए सैन्य कब्ज़े के खिलाफ एक निर्णायक विरोध प्रदर्शन है। इस कब्ज़े की शुरुआत 1949 में चीन के आक्रमण से हुई थी। इसके बाद, 1951 में सैन्य धमकियों के साये में तथाकथित "सत्रह-सूत्री समझौते" को ज़बरदस्ती थोपा गया और 1959 तक पूरे तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया गया। तब से चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत की भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति और पर्यावरण को सुनियोजित तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया है—जो तिब्बत की आज़ादी और संप्रभुता के जीवंत प्रमाण हैं।

दस लाख से अधिक तिब्बतियों को मनगढ़ंत राजनीतिक आरोपों के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाला गया और उनका नरसंहार किया गया। वर्तमान में, चीन की 'चीनीकरण' (Sinicisation) की नीति के माध्यम से ज़बरदस्ती आत्मसातीकरण (assimilation) को आक्रामक रूप से बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में पारित तथाकथित "जातीय एकता और प्रगति संवर्धन कानून" तिब्बती पहचान को मिटाने की एक और सोची-समझी साजिश है। 'ब्लैक हैट मार्च' इन्हीं गंभीर अन्यायों के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक है।

तिब्बत एक प्राचीन सभ्यता और एक अनोखा राष्ट्र है, जो अपनी भौगोलिक संरचना के कारण अपने सभी पड़ोसियों से मौलिक रूप से भिन्न रहा है। विशाल और बर्फ़ीले पहाड़ों से घिरा होने के कारण इसे "दुनिया का तीसरा ध्रुव" और "दुनिया की छत" कहा जाता है।
ऐतिहासिक रूप से, तिब्बत एक शक्तिशाली साम्राज्य और धार्मिक राष्ट्र था, जिसका प्रभाव पूरे एशिया में रहा है। हज़ारों वर्षों के इतिहास के साथ, तिब्बत की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और समृद्ध परंपराएँ हैं। यह क्षेत्र सोना, चांदी, तांबा और जल जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। तिब्बती लोग छह मूल पैतृक कुलों के वंशज हैं, जो चीनी मूल से पूरी तरह भिन्न एक अलग नस्ल हैं।

1959 के अवैध कब्ज़े के बाद से तिब्बतियों ने अकल्पनीय यातनाएं झेली हैं। कम्युनिस्ट तानाशाहों के शासन में "तीन प्रतिनिधित्व" (Three Represents) और शी जिनपिंग के "हान-केंद्रित राष्ट्र निर्माण" जैसी विचारधाराओं के नाम पर तिब्बत के पर्यावरण को नष्ट किया गया है। तिब्बतियों को बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित कर उन्हें असीम शोषण का शिकार बनाया गया है।

तिब्बत न कभी चीन का हिस्सा रहा है और न ही वह तथाकथित "झोंगहुआ नस्ल" का अंग है। यह हमेशा से एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। भारत स्थित 'केंद्रीय तिब्बती प्रशासन' (निर्वासित सरकार) ही स्वतंत्र तिब्बत की शासन प्रणाली की वास्तविक निरंतरता और तिब्बती स्व-शासन की एकमात्र वैध संरक्षक है।

"सामाजिक स्थिरता" के झूठे बहाने चीन तिब्बतियों के मौलिक अधिकारों—जैसे आवाजाही, धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता—का गला घोंट रहा है। चीन ने दुर्भावनापूर्ण साज़िशों के तहत अनगिनत निर्दोष तिब्बतियों पर झूठे आरोप मढ़े हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम 11वें पंचेन लामा, गेदुन चोएकी नीमा का है।

तिब्बती संस्कृति में एक कहावत है: "बेगुनाह के सिर पर षड्यंत्र की काली टोपी पहना देना"। चीनी सरकार ठीक यही कर रही है—निर्दोषों को अपराधी बताकर जेल में डालना और उन पर अत्याचार करना।

Postel Address : Office of the Central Executive Committee
P.O. Mcleod Ganj, Dharamsala - 176219, H.P. (INDIA)
Mob: +91 78077-34959 / +91-7832846846
Email: tyc@tibetanyouthcongress.org
www.tibetanyouthcongress.org

आज स्थिति इतनी चिंताजनक है कि तीन साल तक के बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर 'औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों' में भेजा जा रहा है, जहाँ उन पर कम्युनिस्ट विचारधारा थोपी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा तक बोलने में असमर्थ हो रही है।

तिब्बती युवा कांग्रेस, 12 मार्च 2026 को चीनी राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा पारित "जातीय एकता और प्रगति संवर्धन कानून" की कड़े शब्दों में निंदा करती है। सात अध्यायों और 65 अनुच्छेदों वाला यह कानून वास्तव में सांस्कृतिक नरसंहार का एक कानूनी हथियार है। यह कानून तिब्बतियों को उनकी मौलिक पहचान और आज़ादी से पूरी तरह वंचित करने का प्रयास है।

विशेष रूप से, अनुच्छेद 64 में यह उल्लेख है कि "प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों, नगर पालिकाओं, जिलों और शहरों की जन कांग्रेसें तथा उनकी स्थायी समितियाँ, स्थानीय वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर, जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय नियम बना सकती हैं।" यह स्पष्ट रूप से स्थानीय अधिकारियों को ऐसे कानून लागू करने की शक्ति देता है जो वर्तमान दमनकारी नीतियों से भी अधिक कठोर हो सकते हैं। यह कानून स्पष्ट रूप से दमन के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो एक अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और क्रूर कदम है। इसीलिए, "सितंबर के चौथे सप्ताह को 'राष्ट्रीय एकता और प्रगति प्रचार सप्ताह' के रूप में नामित करने" की इस दमनकारी पहल का विरोध करने के लिए, निर्वासित तिब्बती सरकार ने इस सप्ताह को "तिब्बती पहचान रक्षा सप्ताह" के रूप में मान्यता दी है। तिब्बती युवा कांग्रेस इसके द्वारा यह घोषणा करती है कि इसी सप्ताह को आधिकारिक तौर पर 'तिब्बती नरसंहार सप्ताह' के रूप में मनाया जाएगा। यह उस सुनियोजित प्रयास का प्रतीक है जिसके माध्यम से चीनी कम्युनिस्ट सरकार तिब्बती पहचान और अस्तित्व को मिटाना चाहती है।

तिब्बती युवा कांग्रेस यह दोहराती है कि जब तक तिब्बत की स्वतंत्रता बहाल नहीं हो जाती, हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीनी अन्याय को उजागर करना जारी रखेंगे। हम और अधिक शक्ति और व्यापक स्तर पर विरोध करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। चूंकि तिब्बती संघर्ष की मुख्य जिम्मेदारी स्वयं तिब्बतियों की है, इसलिए हम निर्वासन में रह रहे सभी तिब्बतियों से एकजुट होने का आग्रह करते हैं। हमारे शहीदों और तिब्बत के भीतर संघर्षरत भाइयों की आशाओं को पूरा करने के लिए हमें इस स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हम सभी तिब्बतियों का आह्वान करते हैं कि वे अपनी भाषा, लिपि, धर्म और संस्कृति को गर्व के साथ संरक्षित और प्रचारित करें।

हमें विश्वास है कि अपनी अटूट जिजीविषा के बल पर जल्द ही सभी तिब्बती एक स्वतंत्र तिब्बत में पुनः एकत्रित होंगे। हम निर्वासित तिब्बतियों के प्रति निरंतर समर्थन के लिए भारत सरकार और यहाँ की जनता के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय सरकारों एवं संगठनों के सहयोग की भी सराहना करते हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि जब तक तिब्बत को सत्य और न्याय नहीं मिल जाता, तब तक अपना अडिग समर्थन जारी रखें।
धर्मशाला से दिल्ली (संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) तक पदयात्रा करते हुए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे साथ खड़े हों और #BlackHatMarch के साथ इस संदेश को साझा कर हमारी आवाज़ बुलंद करें।

तिब्बती युवा कांग्रेस की 19वीं कार्यकारी समिति

31 मार्च 2026

Postel Address : Office of the Central Executive Committee
P.O. Mcleod Ganj, Dharamsala - 176219, H.P. (INDIA)

Mob: +91 78077-34959 / +91-7832846846
Email: tyc@tibetanyouthcongress.org

www.tibetanyouthcongress.org